उत्तर कोरिया जैसा दुराग्रही देश: अमेरिकी विशेषज्ञ

भारत को कमजोर करने के लिए पाक ने बनाए आतंकी समूह

वॉशिंगटन। आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर हथियार और धन मुहैया कराता रहा अमेरिका अब पाकिस्तान को एक्सपोज करने में जुटा है। पाक को आतंकवादियों के लिए सुरक्षित शरणस्थली घोषित किए जाने के बाद अमेरिका के पूर्व राजनयिकों और अधिकारियों ने कहा है कि पाकिस्तान ने तालिबान, हक्कानी नेटवर्क और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी समूह बनाए ताकि भारत की स्थिति को कमजोर किया जा सके और युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हितों को बचाया जा सके।

वहीं रिपब्लिकन पार्टी के एक पूर्व सेनेटर का कहना है कि अमेरिका को पाकिस्तान के साथ भी उत्तर कोरिया की तरह ही दुराग्रही देश जैसा व्यवहार करना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका को कट्टरपंथ से निपटने के लिए भारत के साथ एक वृहद गठबंधन करना चाहिए क्योंकि इस्लामाबाद आतंक से निपटने के नाम पर आर्थिक मदद को लेकर अमेरिका को ब्लैकमेल कर रहा है और उसके बावजूद वह आतंकियों को पाल रहा है। साउथ डकोटा के पूर्व अमेरिकी सेनेटर लेरी प्रेसलर ने अपनी किताब नेबर्स इन आर्म्सः एन अमेरिकन सेनेटर्स क्रेस्ट फॉर डिसआर्ममेंट इन न्यूक्लियर सब कॉन्टिनेंट में लिखा है कि आतंकवाद को लेकर अगर पाकिस्तान अपने तरीकों में बदलाव नहीं करता है तो उसे आतंकी देश घोषित कर देना चाहिए। मेरे अलावा विदेश नीति के कई अग्रणी विशेषज्ञों ने भी जोर देकर यह बात कही है। बुश प्रशासन ने भी अपने पहले कार्यकाल में वर्ष 1992 में इस बारे में गंभीरता से विचार किया था।

प्रेसलर ने लिखा कि पाकिस्तान के साथ भी उत्तर कोरिया की तरह दुराग्रही देश जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। पाकिस्तान पूरी तरह से नाकाम देश नहीं है क्योंकि चीन और अमेरिका जैसे देशों ने विदेशी सहायता के रूप में उसे भारी-भरकम आर्थिक सहायता देना जारी रखा है। दूसरी ओर खुफिया समाचार और विश्लेषण के ऑनलाइन पोर्टल द साइफर ब्रीफ के मुताबिक पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत रह चुके विलियम मिलाम और ओबामा प्रशासन में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में दक्षिण एशिया के वरिष्ठ निदेशक रह चुके फिलिप रेनर ने कहा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकवादी समूहों को लगातार सुरक्षा और सहायता दे रही है।

इस पोर्टल ने गुरुवार को ऐसे साक्षात्कार और आलेख डाले जिसमें इंटर सर्विसेस इंटेलिजेंस (आईएसआई) के दोहरे खेल का खुलासा किया गया था। मिलान ने पोर्टल को बताया कि पाकिस्तान की शांतिपूर्ण अफगानिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं है जो उसके पक्के दुश्मन भारत के प्रभाव में होगा और वहां अपने हितों की रक्षा के लिए उसे छद्म रूप की सख्त जरूरत महसूस होती है।

उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि 1990 के दशक के मध्य में तालिबान के गठन के वक्त पाकिस्तान मौजूद था और देश को नियंत्रण में लेने की उसकी लड़ाई को पाकिस्तान ने खासा समर्थन भी दिया। हम जानते हैं कि हक्कानी नेटवर्क जो अफगान तालिबान से जुड़ा है, वह उसके लिए एक बढ़िया छद्म विकल्प बन गया है। मिलाम ने कहा कि यह तर्क कि आईएसआई हक्कानी नेटवर्क, तालिबान और लश्कर-ए-तैयबा जैसे शत्रु समूहों का समर्थन करता है। इसे आमतौर पर पश्चिमी दुनिया के विशेषज्ञ सही मानते हैं, लेकिन इसके सबूत बेहद गोपनीय तरीके से रखे गए हैं। मिलाम वर्ष 1998 से 2001 तक पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत थे।

भारतीय हुए 114 पाकिस्तानी

अहमदाबाद। नंदलाल मेघानी, डॉ. विशनदास मनकानी और किशनलाला अडानी की खुशियों की खुशियों की कोई सीमा नहीं है। ये तीनों उन 114 पाकिस्तानी लोगों में से एक हैं, जिन्हें हाल ही में भारत की नागरिकता मिली है। इन सभी लोगों को शुक्रवार को भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र मिलेगा।

पाकिस्तान में अपराध की दर बहुत अधिक

हमारे सहयोगी अखबार अहमदाबाद मिरर से बात करते हुए घाटलोडिया में रहने वाले 50 वर्षीय नंदलाल मेघानी ने कहा कि 16 साल पहले पाकिस्तान के सिंध से मैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ भारत आ गया था। भारत में नई शुरुआत करने के लिए वहां हमने अपना घर और बिजनस बेच दिया।

हम भारत में आम लोगों की जिंदगी से प्रभावित थे और यहां आकर नागरिकता के लिए आवेदन कर दिया। भारत में शरण लेने की प्रमुख वजह पाकिस्तान में अपराध की उच्च दर है। यही नहीं लगातार बढ़ते आतंकवाद के चलते पाकिस्तान के हमारे मुस्लिम दोस्तों ने भी हमें भारत में शिफ्ट होने के लिए प्रेरित किया। मेघानी पाकिस्तान में ऑटो पार्ट्स का बिजनस करते थे।

आतंकवाद से वहां नरक में तब्दील हो गई थी जिंदगी

पाक से आए 59 वर्षीय किशनलाल अडानी ने कहा कि मैं 2005 में पत्नी और 4 बेटों के साथ भारत आया था। मेरे बेटे कल आ रहे हैं और हम बहुओं समेत भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाइ करने की योजना बना रहे हैं। अडानी पाकिस्तान के सिंध सूबे के थारपकड़ कस्बे में जनरल स्टोर चलाते थे। भारत में अपने बेटों के साथ उन्होंने बर्तन की दुकान शुरू की है। भावुक अडानी ने बताया कि मैं अब भी अपने उस घर और दोस्तों को याद करता हूं, जिन्हें छोड़कर हम यहां आ गए हैं। हालांकि आतंकवाद के चलते हमारे लिए बचे रहना मुश्किल हो गया था। जब हम बाहर निकलते थे तो सोचते थे कि वापस घर आ भी पाएंगे या नहीं।

भारत सुरक्षित और ज्यादा विकसित

पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को नागरिकता देने के मामले में जिलाधिकारियों को अधिकार दिए जाने की तारीफ करते हुए विशनदास मनकानी ने बताया कि 2001 में वह अपने 4 बच्चों के साथ भारत आए थे। मनकानी ने कहा कि मुझे और मेरी पत्नी को 2016 में भारतीय नागरिकता मिली थी।

जयपुर में 7 करोड़ का सोना लूटा, 24 घंटे पहले ही शहर में हुई थी बैंक डकैती

जयपुर। बैंक में 15 लाख की डकैती के 24 घंटे बाद ही शहर में लूट की बड़ी वारदात हो गई। शुक्रवार को मानसरोवर इलाके की मुथूट फाइनेंस कंपनी से 31 किलोग्राम सोना लूट लिया गया। चार बदमाशों ने महज 20 मिनट में लूट को अंजाम दिया। लूटे गए सोने की कीमत 7 करोड़ रुपए बताई गई है।

कैसे हुई वारदात

मुथूट फाइनेंस के ऑफिस में शुक्रवार को रोज की तरह काम हो रहा था। तभी चार बदमाश पहुंचे। कर्मचारियों पर पिस्तौल तान दी। इस वक्त चार लोगों का स्टाफ और दो कस्टमर थे। इन सभी को हथियारों की नोंक पर एक तरफ खड़ा कर दिया गया। बदमाशों ने इसके बाद मैनेजर से लॉकर की चाबी मांगी। इनकार करने पर मारपीट की। बाद में मैनेजर ने चाबी दे दी। बदमाशों ने लॉकर खोलकर सोना निकाला और फरार हो गए।

बीस मिनट में दिया लूट को अंजाम

बदमाशों ने इतनी बड़ी लूट को महज 20 मिनट में अंजाम दिया। बदमाशों ने इतनी तेजी से काम किया कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी।

बदमाशों के जाते ही कर्मचारियों ने हल्ला मचाकर आस-पास के लोगों को बुलाया। पुलिस को सूचना दी। थोड़ी देर में पुलिस पहुंची। नाकाबंदी कराई। एफएसएल टीम ने मौके का मुआयना किया।

सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश

ऑफिस में लगे सीसीटीवी में लूट की वारदात कैद हुई है। चार में से दो बदमाशों ने हेल्मेट लगा रखा था। एक ने चेहरे को रूमाल से ढंका था जबकि एक का चेहरा खुला हुआ था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। बदमाश दो बाइकों पर आए थे और वारदात के बाद इन्हीं पर फरार भी हो गए।

एक दिन पहले हुई थी बैंक डकैती

बता दें कि गुरुवार को ही आदर्शनगर इलाके में यूको बैंक की एक ब्रांच मे डकैती हुई थी। यहां से बदमाश 15 लाख रुपए ले गए थे। पुलिस अभी इस केस की जांच कर ही रही थी कि शुक्रवार को सोने की लूट की वारदात हो गई।

सुषमा के बयान पर चीन ने फिर दी युद्ध की धमकी कहा-डोकलाम से नहीं हटेगी चीनी सेना

नई दिल्ली। चीन और भारत के बीच डोकलाम को लेकर चल रहे विवाद के बीच चीनी के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को झूठा करार देते हुए फिर से युद्ध की धमकी देते हुए कहा कि भारत का डोकलाम से चीनी सेना को हटाना एक सपना ही रह जाएगा। अखबार के संपादकीय में लिखा गया है कि चीन डोकलाम में चल रहे तनाव को लेकर अपना संयम बरकरार रखे हुए है, अगर भारत सीमा से अपनी सेना को नहीं हटाता है तो चीन बिना कूटनीतिक बातचीत के भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है। संसद सत्र के दौरान सुषमा स्वराज ने कहा था कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है लेकिन पहले चीन डोकलाम से सेना हटाए। सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम हैं। उन्होंने चीन को साफ तौर पर कहा है कि पहले डोकलाम से उसे सेना हटानी पड़ेगी, तभी भारत अपनी सेना हटाए जाने पर विचार करेगा। सुषमा स्वराज ने कहा कि सिक्किम-भूटान-तिब्बत ट्राई जंक्शन पर चीन की ओर से हदें पार की जाती हैं, तो ये देश की सुरक्षा पर बड़ा चैलेंज होगा। अखबार में कहा गया कि सुषमा भरे सदन में झूठ बोल रही थीं। सच तो यह है कि भारत ने चीन की सीमा में दखल दिया है। उन्होंने यह झूठ इसलिए बोला क्योंकि वह जानती है कि इस मुद्दे पर भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनामी झेलनी पड़ेगी। सीमा पर सेना की क्षमता पर बातचीत करते हुए कहा कि चीनी सेना भारतीय सेना के मुकाबले काफी आगे है अगर युद्ध की स्तिथि बनती है तो हमारी सेना भारत को धूल चटा देगी।

प्रथम पृष्ठ का शेष

50 साल तक घर-घर...

तुरंत पूरा कर देते हैं। श्री यादव ने क्षेत्रवासियों की तरफ से मुख्यमंत्री से शासकीय विद्यालय को 12वीं तक करने की मांग की। जिसपर मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता से विचार करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र को खुले में शौच मुक्त घोषित कराने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के उत्साहवर्धन के लिए प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने डस्टबिन वितरण योजना की शुरूआत करते हुए कुछ समूहों को गीले एवं सूखे कचरे के लिए हरे और नीले रंग के डस्टबिन वितरित किये। कार्यक्रम में उन्होंने डोर टू डोर ई-रिक्शा, उवला गैस कनेक्शन, डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत उश्रीर्ण प्रमाण पत्र भी वितरित किये।

इस अवसर पर महापौर मधुसूदन यादव, बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष खूबचंद पारख, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामजी भारती, छग्रीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम के अध्यक्ष नीलू शर्मा, छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी के अध्यक्ष अकरम कुरैशी, विधायक डोंगरगढ़ श्रीमती सरोजनी बंजारे, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष सचिन बघेल, राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष रमेश पटेल, राज्य महिला आयोग के सदस्य डॉ. रेखा मेश्राम, नगर निगम के सभापति शिव वर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भरत वर्मा, राजगामी संपदा न्यास के पूर्व अध्यक्ष संतोष अग्रवाल, कोमल सिंह राजपूत, राजेश श्यामकर के अलावा कलेक्टर भीम सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित थे।

करंट की चपेट में आने...

उसने घर में आते ही देखा कि घर के सभी सदस्य एकसाथ गिरे पड़े हैं। उन्होंने किसी अनहोनी की आशंका को भांपकर सीधे पड़ोस के घर में बताने चला गया। पड़ोसियों ने आकर देखा कि सभी लोगों की मौत करंट की चपेट में आने से हो गई। इसके बाद ग्रामीणों और पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मर्ग कायम कर सभी शव को पोस्ट मार्टम के लिए भिजवा दिया है।

दूसरे बेटे जितेंद्र की जान बच गई : मृतकों में राजबती 70 साल पति स्व. कोमल पटेल, मृतका की बड़ी बहू दामिनी 26 साल पति सत्यनारायण पटेल, छोटी बहू चित्ररेखा 23 साल पति जितेंद्र पटेल और सत्यनारायण पटेल 30 साल पिता कोमल शामिल है।

घटना के दौरान राजबती का दूसरा बेटा जितेंद्र मजदूरी करने बाहर चला गया था। इससे उसकी जान बच गई।

तहसीलदार ने कहा मुआवजे का प्रावधान नहीं: दुर्घटना की जानकारी मिलते ही गुरुर थाने की पुलिस और तहसीलदार भी गांव पहुंचे थे। ग्रामीणों ने मृतक परिवार को आर्थिक सहायता और कफन-दफन के लिए शासकीय मुआवजे की मांग की। तहसीलदार ने इस तरह की दुर्घटना में किसी तरह से मुआवजे का प्रावधान नहीं होने का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया।

चंदे की राशि से अंतिम संस्कार की तैयारी

मृतक मजदूर परिवार के पास अंतिम संस्कार के लिए भी पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने स्वेच्छा से चंदा एकत्र कर अंतिम संस्कार की तैयारी की। मृतक परिवार को ग्राम पंचायत की ओर से तीन हजार, सिन्हा समाज की ओर से एक हजार और ग्राम विकास समिति की ओर से 11 सौ रुपए तथा अन्य ग्रामीणों ने अपनी-अपनी हैसियत एवं इच्छा के मुताबिक आर्थिक सहायता दी।

85 लाख की टैक्स...

उक्त विक्रय बीजक के अनुसार 3813365 रू0 का राजस्व शासन को जमा करना था किंतु उसके द्वारा जमा नहीं कर शासन के साथ धोखाधड़ी किया है। उक्त दोनों प्रकरणों में आरोपी राकेश अग्रवाल की गिरफ्तारी की गई है।

66 लाख की टैक्स चोरी कर 2011 से फरार आरोपी गिरफ्तार: एक अन्य मामले में 66 लाख की टैक्स चोरी करने वाले राकेश राम चौधरी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके द्वारा मेसर्स चेतना ट्रेडर्स खुर्सीपार भिलाई के नाम से दिनांक 20 फरवरी 2009 को आयरन एण्ड स्टील, कोक एवं कोल एवं रद्दी पेपर का क्रय-विक्रय करने पंजीयन कराया था। आरोपी राकेश राम चौधरी द्वारा वर्ष 2011 से 2014 के मध्य पंजीयन किया गया फर्म के माध्यम से बोगस बिल जारी किया गया था।

आरोपी के द्वारा चेतना ट्रेडर्स फर्म के माध्यम से अलग-अलग क्रेताओं को 13,31,27,158 रु की सामाग्री बिक्री किया जाना पाया गया। उक्त 13,31,27,158 रू.के विक्रय पर 66,56,358 रुपए का वेट टेक्स के रूप में राजस्व शासन को प्राप्त होना था। वाणिज्यक कर अधिकारी दुर्ग के रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 441/14 धारा 420 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। कायमी बाद से आरोपी फरार था। जिसे गिरफ्तार किया गया।

मोदी की पॉलिसी ने...

कश्मीर मसले पर पाकिस्तान भी एक पक्ष है और उसके साथ बात कर यह मुद्दा सुलझाया जाना चाहिए, इसमें तीसरे पक्ष को भी शामिल किया जा सकता है। ट्रम्प ने खुद कहा है मैं कश्मीर समस्या हल करना चाहता हूं, हमने उनसे नहीं कहा। चीन ने भी कहा कि वे कश्मीर पर मध्यस्थता करना चाहते हैं। कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा बार-बार सीजफायर वॉयलेशन पर श्रीनगर-बडगाम लोकसभा क्षेत्र से सांसद फारूख ने कहा कि जब तक आप कश्मीर पर पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, कश्मीर मुद्दे का हल नहीं निकालेंगे, यह नहीं रुकने वाला है।

हमें यह समझना होगा कि कश्मीर मसले में पाकिस्तान भी एक पक्ष है। कश्मीर में हालात नॉर्मल होने का इंतजार करने के बजाय तुरंत बातचीत कर मामले को सुलझाए जाने की वकालत करते हुए फारूख ने कहा कि सही वक्त का इंतजार करते-करते 70 साल बीत चुके हैं। अब और कितना इंतजार करना होगा। इस दौरान चार युद्ध हो चुके हैं। और कितने लोगों को मरवाएंगे। दोस्तों को इस्तेमाल कीजिए बातचीत करने के लिए।

ट्रेनों और स्टेशनों पर...

बिस्कुट, सीलबंद उत्पाद, मिठाइयां आदि शामिल हैं। इन्हें पीएडी वस्तुएं कहा जाता है और इन्हें लाइसेंसधारी इकाइयों के साथ-साथ विभागीय खानपान सेवा इकाईयों में बेचा जाता है।

महंगी बेची जाती हैं वस्तुएं : रिपोर्ट के मुताबिक यह देखा गया कि ब्रांड का चयन क्षेत्रीय रेलवे द्वारा किया जाता है, लेकिन इनमें मूल्यों का उल्लेख नहीं होता है। ब्रांड के अधिकृत विक्रेता को इस शर्त के साथ एमआरपी पर विक्रय की अनुमति दी गई है कि खुले बाजार में विक्रय किए गए समान उत्पाद की एमआरपी से अधिक नहीं हो। कैग के अनुसार पीएडी वस्तुएं खुले बाजार की तुलना में भिन्न वजन और मूल्य से रेलवे स्टेशनों पर बेची जा रही थीं, जिसमें रेलवे परिसरों में प्रति यूनिट लागत, बाजार के विक्रय मूल्य से बहुत अधिक थी।

नई खान-पान नीति भी बेअसर: रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2005 की खान-पान नीति के अनुसार भारतीय रेल ने खान-पान व्यवसाय को भारतीय रेलवे खान-पान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) को सौंप दिया। साल 2010 में इस नीति में फिर से संशोधन किया गया और भारतीय रेल ने आईआरसीटीसी से फूड प्लाजा एवं फास्ट फूड यूनिटों को छोड़कर सभी खान-पान इकाइयों का प्रबंधन वापस लेने और इन्हें विभागीय रूप से प्रबंधित करने का निर्णय किया। खान-पान सुविधाओं की गुणवत्ता में अपेक्षानुसार सुधार नहीं होने पर रेलवे बोर्ड ने नई खान-पान नीति 2017 को प्रतिपादित की, जिसे 27 फरवरी 2017 में जारी किया गया। इसके बावजूद हालात नहीं सुधर रहे हैं।

रेलवे के कुछ फर्मों का अधिपत्य बढ़ा: कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि ठेकेदारों को ठेका देने के लिये निर्धारित अधिकतम सीमा का पालन न करने से रेलवे ने कुछ फर्मो के अधिपत्य को बढ़ावा दिया। एकाधिपत्य के कारण यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं कीगुणवत्ता से समझौता हुआ। खान-पान नीति में बार बार परिवर्तन और खान-पान इकाईयों के प्रबंधन के उत्तरदायित्व को रेलवे से आईआरसीटीसी को हस्तांतरित करने और वापस लेने के परिणामस्वरूप यात्रियों को प्रदान की जाने वाली खान-पान सेवाओं के प्रबंधन में अस्थिरता की अवस्था उत्पन्न हुई है।

कैग की सिफारिश: कैग ने अपनी सिफारिशों में कहा कि रसोईयानों के निर्माण के दौरान इसमें गैस बर्नर से विद्युत ऊर्जा उपकरणों के अंतरण की नीति को ध्यान में रखा जाए। लंबी दूरी की ट्रेनों के मामले में नीति के अनुसार रसोईयानों के प्रावधान पर विचार किया जाए। रेलवे खानपान इकाईयों को आईआरसीटीसी को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को सुगम बनाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि क्षेत्रीय रेलवे अपने दायित्वों का वहन करे। इसमें कहा गया है कि आईआरसीटीसी को स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में सस्ता जनता खाना प्रदान करने के लिये दायित्वबद्ध किया जाए और यात्रियों के बीच इसे प्रभावी रूप से प्रचारित किया जाए।

स्कूली बच्चों पर फायरिंग किसी आर्मी को शोभा नहीं देती पाक डीजीएमओ से बोला भारत

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में स्कूली बच्चों पर पाकिस्तान आर्मी की फायरिंग के बाद भारत ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। गुरुवार को इंडियन आर्मी के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन (डीजीएमओ) ने अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से कहा कि मासूम स्कूली बच्चों पर फायरिंग किसी आर्मी को शोभा नहीं देती। बता दें कि मंगलवार को राजौरी जिले के नौशेरा में पाकिस्तान की फायरिंग में दो स्कूलों के करीब 200 बच्चे फंस गए थे। आर्मी ने इन्हें बुलेटप्रूफ गाड़ियों में हिफाजत से उनके घर पहुंचाया था।

4 दिन में दूसरी बार हॉटलाइन पर बात

सोमवार को पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल एके. भट्ट को हॉटलाइन पर फोन किया था। गुरुवार को भट्ट ने मिर्जा से फोन पर बात की। स्कूली बच्चों और सिविलियन्स को टारगेट बनाए जाने पर सख्त आपत्ति दर्ज कराई। आर्मी के स्पोक्सपर्सन कर्नल अमन आनंद ने इसकी जानकारी मीडिया को दी। आनंद के मुताबिक, भट्ट ने मिर्जा से कहा कि पाकिस्तान आर्मी बेकसूर सिविलियन्स और स्कूली बच्चों को निशाना बना रही है, उन पर फायरिंग की जा रही है। ये किसी भी आर्मी को शोभा नहीं देता।

अपने जवानों पर कंट्रोल करे पाकिस्तान

कर्नल आनंद के मुताबिक, भट्ट ने पाकिस्तानी काउंटरपार्ट से कहा कि आप अपने ट्रूप्स पर सख्ती से कंट्रोल करें। उन्हें किसी भी गैर जिम्मेदाराना कदम उठाने से रोंके। भट्ट का वॉर्निंग बहुत सीधी थी कि अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता है तो फिर उसे पछताना पड़ेगा। भट्ट ने मिर्जा से कहा कि इंडियन आर्मी बहुत प्रोफेशनल तरीके से पेश आती है और सिविलियन्स को निशाना नहीं बनाती। जबकि पाकिस्तान फायरिंग के जरिए भारत में आतंकी घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है।

4 दिन पहले भी हुई थी बात

दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच सोमवार को भी बातचीत हुई थी। इस दौरान भट्ट ने मिर्जा से कहा था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग और घुसपैठ की कोशिश होती रही तो भारत की तरफ से भी करारा जवाब दिया जाता रहेगा। कर्नल आनंद ने कहा कि भारतीय सेना अपने सिविलियन्स की सेफ्टी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उनकी जान और प्रॉपर्टी की रक्षा करना हमारा फर्ज है। बता दें कि गुरुवार को ही पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में इंडियन एम्बेसी के डिप्टी हाईकमिश्नर को बुलाकर भारत की फायरिंग में अपने नागरिकों की मौत का मामला उठाया था।

इस्तीफे के बाद मायावती ने 23 को बुलाई बसपा नेताओं की बैठक तय करेंगी आगे की रणनीति

लखनऊ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद आगे की रणनीति तय करने के लिए 23 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। दलितों के मुद्दे पर राज्यसभा में बात रखने का मौका न मिलने से नाराज बसपा प्रमुख ने पिछले दिनों अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। कल इस्तीफा स्वीकार होने के बाद मायावती ने दिल्ली में ही रविवार को उत्तर प्रदेश के साथ ही दूसरे राज्यों के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है।

मायावती का इस्तीफा गांव-गांव पहुंचाने की तैयारी

सूत्रों का कहना है दलितों के मुद्दे पर बसपा प्रमुख द्वारा इस्तीफा देने की बात को अब गांव-गांव तक पहुंचाने की तैयारी है। बसपा प्रमुख ने राज्यसभा में जो बोला उसे सोशल मीडिया आदि पर वीडियो के जरिए दलितों के बीच पहुंचाकर यह संदेश देने की कोशिश है कि मायावती ही उनकी सच्ची हितैषी हैं।

दलितों की लड़ाई लड़ने के लिए बसपा प्रमुख ने अपने पद की परवाह नहीं की। दलित हित में सांसदी कुर्बान करने की छवि को उभारने के लिए पार्टी सड़कों पर भी संघर्ष करेगी। 23 जुलाई को दिल्ली में बैठक में इसकी रणनीति तैयार की जाएगी।

सड़कों पर भी संघर्ष की तैयारी

आंदोलन से आमतौर पर दूर रहने वाली बसपा बदले हालात में संघर्ष की राह पकड़ती दिख रही है। विधानसभा में भी बसपा आक्रामक तेवर अपनाए हुए है। उल्लेखनीय है कि खिसकते दलित वोटबैंक के कारण ही पार्टी का लोकसभा और विधानसभा चुनाव में निराशाजनक रहा है।

मायावती के इस्तीफे से राजनीति का माहौल गर्म

बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने बीते मंगलवार को राज्यसभा से अपना इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद देश की राजनीति का माहौल अचानक से गर्म हो गया था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह आरोप लगाया था कि, सहारनपुर मुद्दे में उन्हें बोलने नहीं दिया गया, उन्हें जबरन चुप कराया गया। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा सरकार भी हमला बोला था। मायावती ने आरोप लगाया था कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में देश में दलितों, गरीबों का उत्पीड़न बढ़ा है। इसके साथ ही मायावती ने सहारनपुर का मुद्दा राज्यसभा में उठाया। उनके अनुसार सहारनपुर की घटना सोची समझी साजिश का नतीजा थी।